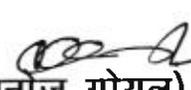


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 240-पीबीआर/15

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-5-2015	<p>आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.2.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है । इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस मुख्यतः इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिये नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । इस सम्बन्ध में तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदक का धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करने के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करना थी, जो नहीं की गई है, इस प्रकार आवेदिका की मौन स्वीकृति है, आवेदिका आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनाज गोयल) अध्यक्ष</p>	

श्री ज्योति पति श्री पी० सी० ममतानी  
 20/1/15 को प्रेषित  
 न्यून 537  
 170

निगरानी 240-PBR-15

निगरानी प्र०क्र० /2015

प्रस्तुती दिनांक 20-01-2015

माननीय अवर राजस्वसेवा न्यायालय (जि.ड.)  
के समक्ष।

श्रीमती ज्योति पति श्री पी० सी० ममतानी  
 निवासी - : 23, कृष्णाकुन्ज कालोनी, पुष्पकुन्ज  
 अस्पताल के पास, खण्डवा रोड इंदौर 491001

--- निगरानीकर्ता  
 प्राथी

विरुद्ध

बेताला हाउसिंग डेवलपमेंट प्रा० लि०  
 द्वारा : निर्देशक <sup>राजस्वसेवा न्यायालय</sup>  
 पता न्यू नंबर 142, पुराना नम्बर 44  
 सुबमनिया मुडलई स्ट्रीट पहली मंजिल  
 सईट पेट वेन्नई तमिलनाडु।

---- प्रतिप्राथी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता प्राथी के द्वारा यह उक्त निगरानी  
 माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, इंदौर के  
 द्वारा प्राथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 32 को  
 दिनांक 13-2-14 को निरस्त किये जाने बाबद आदेश पारित  
 किया गया जिससे असंतुष्ट होकर, निम्न व अन्य आधारों पर  
 प्रस्तुत किया जा रहा है :-

